अन्तर्राष्ट्रीय साजिशों के जाल में फंसता हिमालयी राष्ट्र-नेपाल

योगी आदित्यनाथ
संसद सदस्य (लोक सभा)
-श्री गोरखनाथ मन्दिर, गोरखपुर (उ०प्र०)

सुदूर अतीत काल से जब पुराणों में हिमालय से कन्याकुमारी तक विस्तृत विशाल भूखण्ड को हिन्दुस्थान कहा गया था नेपाल उसी विशाल भूखण्ड के अन्तर्गत प्राचीन काल से ही एक हिन्दू राष्ट्र रहा है। यदि हम नेपाल के इतिहास को देखें तो हमें ज्ञात होता है कि प्रारम्भ से ही शासन चाहे क्षेत्रीय जनजातियों-किरातों का रहा हो चाहे यादवों और अन्य राजवंशों का सभी न्यूनाधिक रूप में हिन्दुत्व निष्ठ थें और वहां की जनता भी हिन्दू-वैदिक शैव, शाक्त-बौद्ध-परम्पराओं देवी देवताओं में रची-बसी हिन्दुत्व की ही अनुयायी रही है। यहां का सामाजिक और धार्मिक ताना-बाना ही नहीं सम्पूर्ण सांस्कृतिक विरासत परम्परागत रूप से हिन्दुत्व से अनुप्राणित और परिचालित रही है जिसके कारण इसकी स्वाभाविक पहचान एक हिन्दू राष्ट्र और देश के रूप में ही है। **इसलिये 18 मई, 2006 का दिन एक संवैधानिक हिन्दू अधिराज्य के रूप में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय रूप में मान्यता प्राप्त नेपाल के इतिहास में निश्चित रूप से एक काले अध्याय के रूप में अंकित किया जायेगा। जब यहां की कंगारू संसद ने एक अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लेते हुये नेपाल को हिन्दू राष्ट्र के स्थान पर एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पारित किया।** अप्रत्याशित इसलिये कि- (1) तीन वर्ष पहले ही अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी प्रयोजन विशेष के लिये बहाल की गयी संसद को ऐसा निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। (2) संवैधानिक राजतंत्र और बहु दलीय लोकतंत्र पर आधारित जिस वर्तमान संविधान को 1990 में पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात्

तत्कालीन संसद ने और जनता ने भी व्यापक समर्थन के साथ स्वीकार किया था उसे आनन-फानन में बिना अधिकारिता के परिवर्तित करके उसके स्थान पर नया प्रावधान स्थापित करने का भी कोई वैधानिक या नैतिक अधिकर इस कंगारू संसद को नहीं है। अच्छा तो यह होता कि राजा द्वारा जनभावना का सम्मान करते हुये जिस भंग संसद को शान्ति-व्यवस्था और लोकतंत्र को विधिवत पटरी पर लाने के लिए बहाल किया गया था वह सर्वप्रथम शान्ति और व्यवस्था को बहाल करती फिर जनता के बीच जाकर वांछित जनादेश प्राप्त करती और जनादेश मिल जाने के बाद संविधान सभा का गठन कर पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लेती। किन्तु ऐसा न करके जिस प्रकार जल्दबाजी में निरंकुशता पूर्वक बलात् हिन्दु राष्ट्र नेपाल को एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया वह न केवल अनुचित और अवैधानिक है बल्कि अनेक पूर्व ग्रहों, साजिशों और दु:शंकाओं को भी पैदा करने वाला है।

नेपाल को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने का उक्त निर्णय दुर्भाग्य पूर्ण इसलिए है कि जिन ताकतों के बाद में जल्दबाजी में यह फैसला किया गया पिछले कई वर्षों से उन माओवादियों, इस्लामिक उग्रवादियों और ईसाई चर्चों की निगाहें नेपाल के हिन्दू चरित्र और अभिज्ञान को मिटाने के लिये मौन-मुखर रूप से सक्रिय थी और उन्होंने ही नेपाल में अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जिसका परिणाम नेपाल के एकीकृत, हिन्दुत्व निष्ठ परम्परागत राष्ट्रवादी स्वरूप को छिन्न-भिन्न कर अपने राजनैतिक, आर्थिक, सामरिक और व्यवसायिक हितों को सिद्ध करना है। आश्चर्य इस बात पर होता है कि बाहर परस्पर युद्धरत ईसाई-इस्लामी और कम्युनिस्ट शक्तियाँ नेपाल के वर्तमान स्वरूप को नष्ट करने के मामले मं नेपाल के अन्दर परस्पर सहयोग करते हुये बन्दरबाँट में लगी हैं।

इस सम्पूर्ण प्रकरण में भारतीय विदेशनीति की विफलता का आकलन करते हुये मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि नेपाल में आज तो ताकतें उभार पर हैं यदि उनका जोर जारी रहा तो यह भारत की एकता और अखण्डता के लिये भी गम्भीर चुनौती होगा। जिस छद्म धम्र निरपेक्षता के नाम पर यह बस वहां हो रहा है वह एक धोखा भर है। वास्तविकता यह है कि नेपाल में 80.62 प्रतिशत वैदिक सनातनी हिन्दू हैं, 10.47 प्रतिशत बौद्ध, 3.60 प्रतिशत किरात और 0.4 प्रतिशत जैनी हैं जिनकी सम्मिलित संख्या जोड़े तों 95 प्रतिशत से अधिक नेपाली हिन्दू व हिन्दू-मूलक धर्म-सम्प्रदायों के अनुयायी हैं। शेष केवल 5 प्रतिशत से कम इस्लाम व ईसाइयत के मानने वाले हैं। यह कितनी आश्चर्यजनक और विडम्बनापूर्ण बात है कि नेपाल में 95 प्रतिशत हिन्दू आबादी होने के बावजूद इसे हिन्दू राष्ट्र के बजाय एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र बनाने की दुहाई देने और वकालत करने वाले लोगों द्वारा इण्डोनेशिया, मलेशिया आदि जिन कई इस्लामिक देशों में गैर मुस्लिमों की जनसंख्या का प्रतिशत नेपाल में गैर हिन्दुओं (मुस्लिमों-ईसाईयों) की तुलना में कई गुना अधिक है वहाँ उन्हें धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने की कहीं कोई कोशिश नहीं हो रही है। दर असल इस्लाभ और ईसाइयत के अनुयायियों और प्रचारकों की केवल एक ही मंशा है कि हमारे अपने ईसाई और इस्लामी राष्ट्र तो हैं ही धर्म निरपेक्षता का नारा देकर गैर ईसाई और गैर इस्लामिक देशों को ईसाइयत और इस्लाम के झंडे के नीचे लाया जाय। भारत में उक्त दोनों मजहबी धर्म मतों का कुचक्र बहुत अर्से से चल रहा है जिसके चलते अनादि काल से सनातन हिन्दु राष्ट्र नहीं बन सका और अब देवतात्मा-हिमालय की गोद में बसा विश्व का एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल इनके निशाने पर है। दर असल नेपाल में अमेरिका और आई०एस०आई० दोनों दो दशक से वहां की जनता की

१९९७ में गोरखपुर में आयोजित विश्व हिन्दु महासंघ के पंचम् महाधिवेशन का एक दृश्य जिसमें गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए साथ में राजमाता श्रीमती विजयाराजे सिंधिया, आचार्य गिरिराज किशोर, योगी आदित्यनाथ जी महाराज, श्री अशोक सिंघल जी एवं कृष्ण गोपाल टण्डन जी

सप्तम विश्व हिन्दु महासम्मेलन (१३-१५ फरवरी,२००५) के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि प्रो. राजेन्द सिंह (रज्जू भईया) (सरसंघ चालक रा. स्वयं सेवक संघ) को स्मृति चिन्ह भेंट करते गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ जी साथ में महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज, स्वामी चिन्मयानन्द जी महाराज एवं विश्व हिन्दू महासंघके तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. कृष्ण गोपाल टण्डन जी

सप्तम विश्व हिन्दु महासम्मेलन, गोरखपुर २००३, के अवसर पर आयोजित विराट हिन्दू संगम के मंच की झलकियां

सप्तम विश्व हिन्दु महासम्मेलन, गोरखपुर २००३, के अवसर पर आयोजितविराट हिन्दू संगम के मंच की एक झांकी जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जगदगुरू संकराचार्य, स्वामी वासुदेवनन्द जी, ब्रह्मलीन परमहंस रामचन्द्र दास जी परम् पूज्य अवेद्यनाथ जी एवं नेपाल के डा०प्रपन्नाचार्य जी आदि विराजमान हैं ।

अशिक्षा, गरीबी और पिछड़ेनपन का लाभ उठा कर खासे सक्रिय हैं। ऐसी कई घटनायें उजागर हुई हैं जिनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह धर्मान्तरण करा कर सामरिक दृष्टि से एशिया के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण भू-भाग में अपना पाँच फैलाना चाह रहे हैं। वर्ष 1991 की जनगणना में पूरे नेपाल में ईसाई मूल के मात्र 46 व्यक्ति थें जबकि वर्ष 2005 तक इनकी संख्या जबर्दस्त छलांग लगाते हुये अब डेढ़ लाख से पार हो गयी है। ऐसा ईसाई चर्चों की रणनीति के तहत हो रहा है जिसके दस्तावेजी साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। यहां यह प्रश्न भी उठना चाहिये कि यदि नेपाल में 5 प्रतिशत गैर हिन्दू-इस्लामी व ईसाई जनसंख्या होने के कारण नेपाल को धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र होना चाहिये तो बंटवारे के बावजूद यदि पश्चिमी पाकिस्तान में 10 प्रतिशत हिन्दू थें औरपूर्वी पाकिस्तान-बांग्लादेश में 30 प्रतिशत हिन्दू थें तो इन्हें धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया? मलेशिया में 60 प्रतिशत इस्लाम को मानने वाले हैं जबकि 20 प्रतिशत हिन्दू और 20 प्रतिशत चीनी मूल के लोग हैं तो 40 प्रतिशत गैर इस्लामी आबादी के बावजूद मलेशिया इस्लामी राष्ट्र क्यों है? इसी तरह अफगानिस्तान में भी काफी संख्या में बौद्ध-हिन्दू और सिख हैं फिर भी वह धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र क्यों नहीं है? इन उदाहरणों से भारत के समान ही अब नेपाल के विरूद्ध भी इस्लामी और ईसाइयत की साजिश स्पष्ट देखी जा सकती है। यदि इसे थोड़ा विचारपूर्वक समझने की कोशिश करें तो यह अमेरिका का कम्युनिस्टों और पाकिस्तान की ही सोची समझी रणनीति है। अमेरिका नेपाल में अपना वर्चस्व कायम कर एशिया की दो उभरती हुई शक्तियों - भारत व चीन दोनों को नियंत्रित करने की योजना पर काम कर रही हैं। इनके हित अलग-अलग हैं किन्तु इनकी मंशा एक ही है। इस बात को भारत की सरकार को गम्भीरता से समझना चाहिये अन्यथा वह दिन दूर नहीं

जब इसकी 1751 किमी० लम्बी उत्तरी सीमा पर एक और तिब्बत या कश्मीर खड़ा होगा।

हमें तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के सन्दर्भ में भी गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कश्मीर में आज जो कुछ हो रहा है वह इसी धर्म निरपेक्षता की देन है। कभी धरती का स्वर्ग कहलाने वाला यह भू-भाग आज नरक में तब्दील हो गया है। जब तक कश्मीर में हिन्दू राजा था वहां के अल्पसंख्यक हिन्दू व बहुसंख्यक मुसलमान आबादी भाई-चारे के साथ शान्ति और सद्भावनापूर्वक वहाँ सदियों से रहते थें। किन्तु जैसे ही धर्म-निरपेक्षता का भूत वहाँ भी चढ़ा वह पूरा क्षेत्र इस्लामी आतंकवादियों का कहर झेल रहा है। लाखों की संख्या में कश्मीर घाटी के पुश्तैनी अधिवासी घर-जमीन व इज्जत के साथ ही जान गवाँकर विस्थापित होने को विवश हो गये। पूर्वोत्तर भारत का भी कमोवेश ऐसा ही हाल है। वहाँ ईसाई मिशनरीज द्वारा कराये व्याकपक धर्मान्तरण के बाद जो हालात पैदा हुये हैं वे आज की सुरक्षा, एकता और अखण्डता को लगातार चुनौती देते दिखाई पड़ रहे हैं।

धर्म निरपेक्षता की कीमत भारत से ज्यादा शायद ही किसी देश ने चुकायी हो। भारतीय संसद पर हमला हुआ, हिन्दुओं के तीन सबसे बड़े अराध्य स्थल श्री राम-कृष्ण एवं शंकर जी के तीर्थ स्थलों में से अयोध्या व काशी में हमले हुये, जम्मू के रघुनाथ मन्दिर पर, गुजरात में अक्षरधाम मन्दिर पर हमले हुये। क्या दुनिया के किसी अन्य देश में इसके बावजूद वहाँ का अल्पसंख्यक समुदाय-विशेष सुरक्षित रहता। निश्चित रूप से नहीं। इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। अमेरिका के 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर' पर हुये इस्लामी आतंकवादी हमले का परिणाम बर्बाद अफगानिस्तान व ईराक रूप में हमारे सामने हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर-पंथ निरपेक्ष समाज

हिन्दू ही है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी भारी कीमत चुकाने पर भी बदले की भावना से आंख मूद कर किसी निरपराध पर हमला नहीं किया, बल्कि मनुष्यता का सम्मान रखा। मैं अपनी बात को कुछ स्पष्ट उदाहरणों के साथ विस्तारित करना चाहता हूँ। 8वीं शताब्दी में ईरान पर इस्लाम का हमला हुआ वहां से भाग कर पारसी समुदाय के लोग भारत आये। वे हमारे धर्म बन्धु नहीं थें-उनके आचार-विचार, खा-पान आदि भी हमसे भिन्न थें किन्तु हमने उन्हें पूरी ईमानदारी से उदारतापूर्वक हर सम्भव सहायता दी जिससे भारत में उनका पुर्नवास हो सका। इस्लामी कट्टरता के करण अपने मूल देश में आज कोई पारसी नहीं है किन्तु अब भी हिन्दू समाज में अच्छी खासी संख्या में हैं-फल-फूल रहे हैं और उनमें टाटा जैसे सम्मान्य उद्योगपति और सोली सोराबजी जैसे देश के सालिसिटर जनरल भी हुये हैं। तिब्बत का मामला अभी ताजा उदाहरण है। चीन के दमन से भागे दलाईलामा और उनके तमाम अनुयायियों को भारत में ही शरण मिली, किन्तु हिन्दुओं को धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाने वालों से हमारी सलाह है कि वे कृपा कर उन्हें धर्म निरपेक्षता या सेकुलरवाद का पाठ पढ़ाये जो पैगम्बर औ यीशू के नाम पर कई इस्लामी और ईसाई राष्ट्र बनाये हुये हैं और इतना ही नहीं दूसरे धर्ममत को मानने वालों को न केवल काफिर व दोजख का अधिकारी कहते हैं बल्कि उन्हें सजा देने और कत्ल करने की भी इजाजत देते हैं। धर्म-निरपेक्षता के अलम्बरदार-'दारूल-हरब' को 'दारूल-इस्लाम' में तब्दील करने के लिये दिन रात एक किये इस्लाम के अनुयायिओं को, उनके पोषक इस्लामी राष्ट्रों से धर्म-निरपेक्षता का पाठ पढ़ायेंगे या शिक्षा और सेवा की आड़ में प्रलोभन देकर धर्मान्तरण कराने वाले ईसाई चर्चों और इनके अनुयायिओं को भी सेकुलर बनाने का कार्य करेंगे? शायद नहीं। 1999 में पोप जान पॉल द्वितीय ने भारत

के दौरे के समय कहा था कि यह सहस्राब्दी एशिया में व्यापक धर्मान्तरण की सहस्राब्दी है। पोप यह भी जानते थे कि यह एशिया में कहां सम्भव है। क्यों कि चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अरब देशों में तो इसकी इजाजत है नहीं, इतना ही नहीं धर्मान्तरण कराने वालों के लिये फांसी की सजा भी तय है। इसलिये उनका लक्ष्य हिन्दू राष्ट्र नेपाल और बहुसंख्यक हिन्दू आबादी वाला देश भारत ही है। आज यही कारण है कि अमेरिका और ईसाई मिशनरीज के निशाने पर नेपाल प्राथमिकता पर आ गया है। वस्तुतः अमेरिका नेपाल को सामरिक दृष्टि से अपने लिये महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि वहीं से वह भारत व चीन पर अपनी गतिविधियों को अंजाम देना चाहता है और इस काम के लिये हिन्दू राष्ट्र नेपाल का धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र होना आवश्यक और उसकी योजनाओं के कार्यन्वयन के लिये सुविधाजनक है। इसलिये ईसाई चर्चों के साथ वह भी नेपाल के हिन्दू स्वरूप और चरित्र को समाप्त कर उसे यथाशीघ्र ईसाई बहुल बनाना चाहता है। हिन्दुत्व और हिन्दू राष्ट्र के विरूद्ध ईसाईयों की तरह ही इस्लामी कट्टरपंथी भी भारत के साथ अब नेपाल में भी सक्रिय हैं। देखते-देखते न केवल नेपाल में मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है बल्कि भारत से लगी नेपाल की लम्बी सीमा पर तमाम मस्जिदें व मदरसे खुलते जा रहे हैं जहां से उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण के अलावा अवैध गतिविधियों को भी जारी रखने में सुविधा होती है और उनके इस क्रम में कई अन्य इस्लामी संगठनों के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अहम् सहयोगी हैं। अमेरिका की तरह ही इनके भी अपेन निहित स्वार्थ हैं जो नेपाल के धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होने पर ही सिद्ध हो सकते हैं। इन्होंने अपने सपने के देश युगलिस्तान का नक्सा भी जारी किया है जिसमें पाकिस्तान समेत भारत होते हुये बांग्लादेश तक के भू-भाग सम्मिलित हैं। नेपाल की

सप्तम विश्व हिन्दु महासम्मेलन
(१५ फरवरी,२००३)
के अवसर पर
आयोजित विराट हिन्दु संगम
में उपस्थित
विशाल जन समुदाय
का एक दृश्य

अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिन्दु महासंघ के रजत जयंती समारोह के अवसर पर महासंघ के अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय बूढ़ानील कण्ठ, काठमाण्डू (नेपाल) में महासंघ की भारतीय इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ जी को जनकपुर धाम (नेपाल) का स्मृति चिन्हभेंट करते वहाँ के श्री महन्त साथ में महासंघ के अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जनरल भारत केशर सिंह अन्तर्राष्ट्रीय महासचिव दिवाकर चन्द जी एवं अन्तर्राष्ट्रीय इकाई के राष्ट्रीय महासचिव डा० कुंवर नरेन्द्र प्रताप सिंह

अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिन्दु महासंघ के रजत जयंती समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में महासंघ की भारतीय इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मान चिन्ह भेंट करते हिन्दुआराज्य नेपाल के महाराजाधिराज श्री ५ सरकार-श्री ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह एवं उनके बगल में खड़ी श्री ५ सरकार-महारानी शोभराज्य लक्ष्मी देवी जी

हिन्दू अधिराज्य नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने के विरुद्ध (अन्तर्राष्ट्रीय) विश्व हिन्दु महासंघ के तत्वावधान में काठमाण्डू नेपाल में आयोजित सन्त-सम्मेलन १५ सितम्बर २००६ का एक दृश्य मंच पर विराजमान हैं महासंघ के अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत केशर सिंह, भारतीय इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ जी एवं अन्य

सप्तम विश्व हिन्दु महासम्मेलन
(१५ फरवरी,२००३)
के अवसर पर
आयोजित विराट हिन्दु संगम
में उपस्थित
विशाल जन समुदाय
का एक दृश्य

अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिन्दु महासंघ के रजत जयंती समारोह के अवसर पर महासंघ के अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय बूढ़ानील कण्ठ, काठमाण्डू (नेपाल) में महासंघ की भारतीय इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ जी को जनकपुर धाम (नेपाल) का स्मृति चिन्हभेंट करते वहाँ के श्री महन्त साथ में महासंघ के अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जनरल भारत केशर सिंह अन्तर्राष्ट्रीय महासचिव दिवाकर चन्द जी एवं अन्तर्राष्ट्रीय इकाई के राष्ट्रीय महासचिव डा० कुंवर नरेन्द्र प्रताप सिंह

अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिन्दु महासंघ के रजत जयंती समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में महासंघ की भारतीय इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मान चिन्ह भेंट करते हिन्दुआराज्य नेपाल के महाराजाधिराज श्री ५ सरकार-श्री ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह एवं उनके बगल में खड़ी श्री ५ सरकार-महारानी शोभराज्य लक्ष्मी देवी जी

हिन्दू अधिराज्य नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने के विरुद्ध (अन्तर्राष्ट्रीय) विश्व हिन्दु महासंघ के तत्वावधान में काठमाण्डू नेपाल में आयोजित सन्त-सम्मेलन १५ सितम्बर २००६ का एक दृश्य मंच पर विराजमान हैं महासंघ के अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत केशर सिंह, भारतीय इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ जी एवं अन्य

विश्व हिन्दु महासंघ (अन्तर्राष्ट्रीय)
के तत्वावधान में काठमाण्डू
नेपाल में
हिन्दु राष्ट्र नेपाल को धर्म निरपेक्ष
राष्ट्र घोषित करने के विरोध में
आयोजित सन्त-सम्मेलन
(दिनांक १४ सितम्बर २००६)
में उपस्थित सन्तों एवं
हिन्दु राष्ट्र समर्थकों का एक दृश्य

विश्व हिन्दु महासंघ (अन्तर्राष्ट्रीय)
के तत्वावधान में काठमाण्डू नेपाल
में हिन्दु अधिराज्य नेपाल को
धर्म निरपेक्षराष्ट्र घोषित
करने के विरुद्ध आयोजित
संत-सम्मेलन (१४ सितम्बर २००६)
में नेपाल को पूर्ववत् हिन्दु राष्ट्र
घोषित करने के प्रस्ताव को
समर्थन करते संत एवं
हिन्दु राष्ट्र के नागरिकगण

विश्व हिन्दु महासंघ (अन्तर्राष्ट्रीय)
के तत्वावधान में काठमाण्डू नेपाल में
हिन्दु अधिराज्य नेपाल को धर्म निरपेक्ष
राष्ट्र घोषित करने के विरुद्ध आयोजित
विश्व हिन्दु युवा सम्मेलन कार्यक्रम का
एक दृश्य मंच पर दिखाई दे रहे
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
योगी आदित्यनाथ जी, अन्तर्राष्ट्रीय
अध्यक्ष जनरल भारत केशर सिंह जी
डा० प्रपन्नाचार्य ज्यू,
डा० कुंवर नरेन्द्र प्रताप सिंह
एवं अन्य ।

उक्त विश्व हिन्दु युवा सम्मेलन
(काठमाण्डू) में सभागार
में उपस्थित जन समुदाय
का एक दृश्य

नेपाल को हिन्दु राष्ट्र बनाने के समर्थन में
नेपाल की राजधानी काठमाण्डू की सड़कों पर उतरे
राष्ट्र भक्तों के विरोध मार्च के कुछ दृश्य

मार्च का नेतृत्व कर रहें हैं
योगी आदित्यनाथ जी महाराज
माननीय भारत केशर सिंह
डा० आर० पी० सिंह
राकेश सिंह पहलवान आदि

वर्तमान आबादी के पीछे ईसाई व इस्लामी ताकतों के अलावा माओवादी कम्युनिस्टों की भी अहम भूमिका है। इनका सपना है 'माओलैण्ड' और यह माओलौण्ड नेपाल से लगायत भारत के पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश होते हुये कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र आदि तक शासन स्थापित करने की अवधारणा पर आधारित है जिसके नक्से भी इन्होंने प्रकाशित किये हैं। नेपाल के ताजा घटनाक्रम में इन उपर्युक्त शक्तियों की साजिश को पुनः-पुनः समझने की जरूरत नेपाल और भारत दोनों देशों के लोगों के लये नितान्त आवश्यक है अन्यथा समय रहते उपाय न करने पर बाद में तिब्बद और कश्मीर की तरह पछताना ही पड़ेगा। किन्तु दुर्भाग्यवश नेपाल की तथा भारत की जनता व सरकारें इनके नापाक इरादों की तरह से अपनी आंखे मूंदे हुये है इसलिये निरन्तर साजिश में लगी हुई ताकतें प्रकट रूप में माओइस्ट आतंकवादी छद्म धर्म निरपेक्षता और बहुदलीय लोकतांत्रिक पार्टियों की आड़ में अपने-अपने उद्देश्यों में सफल होती दिख रही हैं। यद्यपि इनकी संख्या महज 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत है फिर भी इनकी संगठित शक्ति के आगे छोटा सा देश नेपाल बुरी तरह प्रभावित होकर हतप्रभ खड़ा हैं।

भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी नेपाल के वर्तमान बदलाव और घटनाक्रम पर भी हमें निगाह रखनी होगी। नेपाल से लगती 1751 किमी० लम्बी भारत की सीमा रेखा है। अब तक हम बिना सेना व अन्य रक्षा उपायों/उपकरणों के इस लम्बी सीमा की तरफ से निश्चिन्त थें क्योंकि नेपाल न केवल मित्र राष्ट्र है बल्कि दोनो देश चिरकाल से साझा सांस्कृतिक विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में सहोदर भाईयों जैसे रहे हैं किन्तु अब आगे शायद ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि नेपाल में सम्प्रति

सक्रिय और प्रभावी शक्तियां भारत की हितैषी नहीं हैं। इतना ही नहीं वे सीमावर्ती क्षेत्र में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर हमारे हितों पर निरन्तर आघात करने की ताक में भी रहेंगी। कहने की आवश्यकता नहीं कि जिस तरह नेपाल के हिन्दू चरित्र व स्वरूप को समाप्त करने का षड़्यंत्र चल रहा है वह नेपाल के साथ ही हमारी साझा संस्कृति, विरासत और भाई-चारे तथा मुक्त आदान-प्रदान को भी बुरी तरह प्रभावित करने वाला है। यह वैसे ही तर्ज पर है जैसा- 'यूनान, मिश्र, रोम सब मिट गये जहां से' के सन्दर्भ में लिखा जा चुका है। इसलिये हमारी चिन्ता भी यही है - फिलहाल नेपाल में विश्व की एक प्राचीनतम् संस्कृति कतो मिटाने का कुचक्र चलाया जा रहा है फिर भारत निशाना बनेगा और धर्मान्तरण और अराजकता शुरू होगी, फिर मुगलिस्तान और 'माओलैण्ड' की स्थापना के लिये जंग शुरू होगी तब शायद धर्म-निरपेक्षता और तुष्टिकरण का शिकार भारत का एक बड़ा भू-भाग कश्मीर से भी बुरी हालत में पहुंच जायेगा। कश्मीर में तो हम फिलहाल पाकिस्तान से लड़ रहे हैं मगर यहां हमारा मुकाबला तीन बड़ी ताकतों से होगा। ऐसे में हालात की भयावह कल्पना की जा सकती है।

वस्तुतः इस सन्दर्भ में कुछ लोग यह कह सकते हैं कि आज नेपाल में जो कुछ हो रहा है वह नेपाल की वर्तमान सरकार कर रही है और इसे व्यापक जनसमर्थन प्राप्त है किन्तु यह बात सत्य नहीं है। हम ऐसा कहने-समझने वालो से पूछना चाहते हैं कि क्या एक ऐसी सरकार को जो राजा द्वारा मनोनीत हो और जिसे सीधे जनता से जनमत संग्रह या चुनाव के माध्यम से जनादेश न मिला हो और जिसे शान्ति व्यवस्था कायम कर संवैधानिक बहुदलीय लोकतंत्र को पुनः पटरी पर लाने के लिये ही बहाल किया जाता हो उसे क्या राष्ट्र की विचारधारा को, हिन्दू चरित्र को या संवैधानिक राजशाही को समाप्त करने का बिना

नया जनादेश प्राप्त किये ऐसे निर्णय लेने का अधिकार है? शायद नहीं। इसलिये पूर्वग्रह या दुराग्रह छोड़कर देश व संविधान के मूल ढांचे को पुनः प्रवर्तमान करने के लिये हमें अपनी शक्तियों का उपयोग कर प्रयास करना चाहिये। कुछ लोग नेपाल की वर्तमान घटनाओं के लिये राजा व राजशाही को भी उत्तरदायी मानते हैं, किन्तु ऐसा मानना अतिरंजित है और वस्तुस्थिति से अपरिचित होने के ही कारण ही संभव है। क्योंकि राजा ने जो भी किया अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों के अन्तर्गत विवश होकर किया। फरवरी 2002 से जब नेपाली संसद भंग की गयी थी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ही सरकार चलाने से हाथ खड़ा कर दिया था। इतना ही नहीं उन्होंने माओवादी आन्दोलन को शान्त करने तथा समय से नया चुनाव कराने में भी अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। ऐसी परिस्थिति में संसद भंग करने, माओवादी आतंकवाद पर नियंत्रण कर निश्चित समय के अन्दर नया चुनाव कराने व बहुदलीय लोकतंत्र को स्थापित करने की स्पष्ट घोषणा के साथ राजा ने संविधान सम्मत कदम उठाये थें। उन्होंने इस दिशा में पहल भी की किन्तु जनविश्वास खो चुके राजनैतिक दलों ने उनका सहयोग नहीं किया और इतना ही नहीं उन्हेंने राजा और राजशाही के खिलाफ माओवादी उग्रवादियों से हाथ भी मिला लिया। ऐसी स्थिति में राजा ने पुनः शान्ति व्यवस्था कायम करने तथा परिस्थितियों को सामान्य कर नया चुनाव एवं जनादेश प्राप्त करने के लिये विघटित संसद को पुनः बहाल कर दिया। अब नेपाल की सात दलों की वर्तमान सरकार का यह कर्तव्य था कि वह शान्ति व्यवस्था कायम करने, नया जनादेश प्राप्त करने के लिये चुनाव कराने की दिशा में कदम उठाता। किन्तु माओवादी उग्रवादियों के दबाव में उसने संवैधानिक राजतंत्र तथा नेपाल के हिन्दू अधिराज्य के स्वरूप को समाप्त करने का जो निर्णय लिया वह कदापि उचित एवं संविधान सम्मत

वैधानिक कृत्य नहीं कहा जा सकता है। इसके पहले भी 1990 में एक बार नेपाल के हिन्दू अधिराज्य के स्वरूप को समाप्त करने के लिये प्रयत्न हुआ था किन्तु तब इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी और अनेक धर्माचार्यों तथा हिन्दू नेताओं ने हस्तक्षेप किया था। गोरक्षपीठाधीश्वर श्री महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने भी तत्कालीन नेपाल नरेश तथा संविधान सभा के अध्यक्ष से मिल कर नेपाल के हिन्दू चरित्र को यथावत कायम रखने की सिफारिश की थी जिसे स्वीकार करते हुये चार बातों पर सहमति बनी थी। **इन चार बातों में एक बात यह थी कि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो और यहां का संवैधानिक प्रमुख हिन्दू राजा हो। अन्य बातों में धर्मान्तरण और गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध की बातें भी शामिल थीं जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया था। हम चाहते हैं कि सहमति के इन बिन्दुओं का समादर हो** और नेपाल का हिन्दू चरित्र कायम रहे और राजनैतिक दलों की विफलता के लये अनावश्यक रूप से किसी एक व्यक्ति को दोषी न ठहराया जाय।

चीन से शस्त्र खरीदने का दृष्टान्त देकर भी कुछ लोग नेपाल नरेश पर यह आरोप लगाते हैं कि वह भारत के बजाय चीन की तरफ झुकाव रखते हैं। चीन से हथियार खरीदने का निर्णय नेपाल ने तब लिया जब मजबूरी में भारत सरकार ने किसी भी प्रकार का सहयोग करने से इन्कार कर दिया था। जैसा कि विदित है कि 1950 में भारत और नेपाल के बीच 'ट्रीटी आफ पीस एण्ड फ्रैण्डशिप' हुई थी। उसमें यह कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे की सम्प्रभुता की रक्षा करते हुये थी। उसमें यह कहा गया है कि दोनों मे नेपाल को उसकी जरूरत के हथियारों के तीन चौथाई हिस्सों की आपूर्ति की भी व्यवस्था है। मगर गाढ़े वक्त में माओवादी आतंक और अराजकता से निपटने के लये राजा ने भारत से शस्त्र मागें तब भारत सरकार ने लोकतंत्र व धर्म निरपेक्षता की दुहाई

देकर नेपाल को असहाय स्थिति में छोड़ दिया। ऐसी हालत में राज के सामने दो ही विकल्प थें- या तो माओवादी आतंक और अराजकता के समक्ष घुटने टेक दें या फिर चीन से आवश्यक हथियार मांगें। भारत सरकार के उक्त निर्णय का मूल्यांकन भविष्य की घटनाओं से होगा किन्तु आज इसका विश्लेषण यही है कि भारत ने अपना एक सच्चा मित्र खो दिया। साथ ही यह देश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चूक भी साबित हो सकता है। नेपाल में डा० कर्ण सिंह जी ने सही पहल की थी। वह संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र की बहाली के लिये भारत सरकार द्वारा प्रयास किये जाने के हिमायती थें किन्तु कम्यूनिस्टों के दबाव में ऐसा नहीं हो पाया और हिंसा पर उतारू ताकतों का मनोबल बढ़ता चला गया।

नेपाल के वर्तमान संदर्भ के परिप्रेक्ष में नेपाली संसद भंग होने के बाद हमने 120 सांसदों के हस्ताक्षरों से युक्त एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को दिया था। हमसे तब उन्होंने इस मसले पर गम्भीर पहल करने की बात की थी किन्तु पुनः कम्युनिस्टों के दबाव के चलते भारत सरकार पीछे हट गयी। हम समझते है कि उनके दूरगामी परिणाम देश के हित में नहीं होंगे। हमने स्वयं नेपाल के महाराजाधिराज से वार्ता की थी और उनसे भी यह कहा था कि नेपाल का भारत से बड़ा कोई हितैषी नहीं हो सकता है और दोनों देशों को एक दूसरे की सम्प्रभुता और साझी सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्य रखने के लये प्रयास करना चाहिये। तब राजा ने भी हामी भरी थी और भारत सरकार से इस दिशा में बात करने को कहा था। तब से अब तक बागमती में काफी पानी बह चुका है। अब वहां भंग संसद बहाल हो चुकी है और कई बार प्रधानमंत्री रह चुके अनुभवी राजनेता श्री गिरजा प्रसाद कोईराला प्रधानमंत्री हैं। वे अभी भारत के दौरों पर आये

थें। यह एक सुअवसर था कि भारत सरकार दोनों देशों के आपसी हितों के बारे में नेपाल के संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र के बारे में–माओवादी, उग्रवादियों की राजनीति के बारे में, ईसाई चर्चों की मंशा, आई०एस०आई० की गतिविधियों और अमेरिका की रणनीति पर भी स्पष्ट बात करती, किन्तु ऐसा नहीं हुआ। हमारीं समझ से अभी भी वक्त है। भारत सरकार ने कभी निरंकुश राणाशाही का अन्त कर श्री पांच सरकार को नेपाल की सत्ता दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। आज हालात तब से काफी खराब हैं। माओवादी आज नेपाल नरेश को अपदस्थ कर उन्हें फांसी देने की मांग कर रहे हैं, संवैधानिक राजतंत्र को सर्वथा समाप्त करने के लिये दबाव बनाये हुये हैं और दबाव डाल कर राजा के अधिकारों में कटौती के कई प्रस्ताव संसद में पारित भी कर चुके हैं। उनकी मंशा अन्ततः बहुदलीय लोकतंत्र को भी समाप्त कर सत्ता अपने हाथ में लेने की है। ऐसी स्थिति में भारत को मित्र राष्ट्र नेपाल और अपने भी हितों को ध्यान में रखते हुये तत्काल दखल देते हुये नेपाल सरकार को सलाह व हिदायत देनी चाहिये कि वह जल्दबाजी में बिना किसी वैधानिक अधिकार जनादेश के नेपाल के वर्तमान संविधान से छेड़छाड़ न करें क्योंकि दोनों ही देशों के हित में संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र आवश्यक है। किन्तु यदि समय रहते ऐसा नहीं हुआ तो मामला हाथ से निकल जायेगा और भारत सरकार देश की 1751 किमी० लम्बी उत्तरी सीमा पर गहराते संकटों से जूझते रहने के लिये बाध्य होगी।

❑❑❑